Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to make public the census details of Other-Backward Classes in the country.

श्री राजीव सातव (हिंगोली)ः संविधान में ओबीसी समुदाय के सामाजिक और शैक्षिक विकास की परिकल्पना की गयी है। एनडीए सरकार ने केवल ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति को जारी किया है और विशेष रूप से ओबीसी जाति से संबंधित आंकड़े को प्रकाशित नहीं किया है। देश में ओबीसी आबादी पर आंकड़ों की अनुपस्थिति के कारण उनके संपूर्ण विकास के लिए नीति के निर्माण में बाधा हो रही है। ओबीसी समुदाय का विकास देश के विकास से जुड़ा हुआ है। सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव किया है जिसके कारण ओबीसी जनगणना के आंकडों को जारी करने की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह के उपाय से बड़े पैमाने पर ओबीसी समुदाय को लाभ होगा। मैं सरकार से जनगणना के आंकड़ों को जारी करने और उसके आधार पर कल्याणकारी योजनाओं के त्वरित और लक्ष्य आधारित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए अनुरोध करता हूँ।